

विश्वविद्यालय डिजिटलइजेशन का कार्य प्राथमिकता से करें - राज्यपाल

लखनऊ: 01 मार्च, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री राम नाईक ने उच्च शिक्षा को अधिक पारदर्शी एवं एकरूप बनाने के लिये प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में डिजिटलइजेशन - कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया के अधिक से अधिक प्रयोग पर जोर दिया है। राज्यपाल द्वारा उच्च शिक्षा को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देते हुये प्रो० विनय पाठक, कुलपति, डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में एक दो सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है जिसमें प्रो० सुरेन्द्र दूबे, कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी तथा श्री सुदीप बनर्जी, विशेष कार्याधिकारी (आई०टी०) राजभवन, लखनऊ को नामित किया गया है।

इसी क्रम में श्री राजवीर सिंह राठौर विशेषकार्याधिकारी (शिक्षा) एवं श्री सुदीप बनर्जी विशेष कार्याधिकारी (आई०टी०) राजभवन द्वारा 21 फरवरी, 2017 को डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं 27 फरवरी, 2017 को लखनऊ विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया। राज्यपाल ने शीघ्र ही अन्य विश्वविद्यालयों के निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये हैं।

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के निरीक्षणोपरांत सदस्यों ने प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाव देते हुये कहा है कि सम्बद्ध महाविद्यालयों से उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने हेतु अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर यह प्रावधान किया जाये कि सम्बद्ध महाविद्यालय के स्तर पर ही विषयवार कोडिंग करके एक लिफाफे में तथा उपस्थिति शीट को संलग्न करते हुए दोनों को दूसरे लिफाफे में विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाये ताकि सॉर्टिंग (Sorting) में होने वाली गलतियों एवं इसमें लगने वाले समय की भी बचत हो। प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर पुरानी एवं नई प्रणाली पर आने वाले व्ययभार का तुलनात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाये। महाविद्यालयों की रैंकिंग के सन्दर्भ में मानकों का समावेश ऑनलाइन प्रणाली में हो जिससे छात्र को काउन्सिलिंग के समय ही महाविद्यालयों के तुलनात्मक विश्लेषण के पश्चात चयन में आसानी हो। मास्टर डेटा को सर्वर में पूर्ण करने के पश्चात ही उत्तर पुस्तिकाओं को कटिंग एवं प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाये।

सदस्यों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के निरीक्षण से संबंधित रिपोर्ट में सुझाव दिये हैं कि वर्तमान सत्र में जिन शिक्षकों द्वारा विषय विशेष के प्रश्न पत्र निर्धारित किये गये हैं मात्र उन्हीं से परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न कराया जाये। परीक्षा प्रश्न पत्र की प्रोसेसिंग व्यवस्था को तत्काल सुदृढ़ किया जाये। परीक्षा साफ्टवेयर में इंगित की गयी खामियों को दूर करवाना तथा थर्ड पार्टी वेण्डर द्वारा छात्रों के संवेदनशील डेटा का संरक्षण तथा प्रोसेसिंग को विश्वविद्यालय में ही करवाया जाये। प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर पुरानी एवं नई प्रणाली पर आने वाले व्ययभार का तुलनात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाये। वर्तमान सत्र में मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों की सूची उपलब्ध करायी जाये। आगामी शैक्षिक सत्र 2017-18 की सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन सुनिश्चित की जाये तथा इसे आधार से लिंक किया जाये। आगामी सत्र 2017-18 से यह सुनिश्चित किया जाये कि पाठ्यक्रम निर्धारण से लेकर मूल्यांकन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिगत अधिकाधिक शिक्षकों का उपयोग किया जाये तथा आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना तकनीकी तंत्र विकसित करे। इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो तकनीकी परामर्श डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अंजुम/ललित/राजभवन (71/01)